

न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया., और न्यायमूर्ति आर.एन.मिस्तल के समक्ष

धनपत ऑयल एंड जनरल मिल्स-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी।

1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 35।

29 नवंबर 1978.

उत्पाद उपकर अधिनियम, (1966 का XV) - धारा 3(2), 4, 5(1), (2), 9(2) और 20 - उत्पाद उपकर नियम 1969 - नियम 6 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 266 और 272 - धारा 3(2) के तहत लगाया गया उपकर - चाहे वह शुल्क की प्रकृति का हो और इसलिए संसद की शक्ति के बाहर हो - ऐसा उद्ग्रहण - चाहे वह भारत की संचित निधि का हिस्सा हो - शब्द "उपकर" - चाहे वह आवश्यक रूप से शुल्क का वर्णन करता हो - धारा 5- क्या राज्यों को उनके क्षेत्र के भीतर एकत्र किए गए शुल्क के अपने हिस्से को सुरक्षित करने से वंचित करता है - अनुच्छेद 272 का जनादेश - क्या उल्लंघन किया गया है - कानून की किताब पर पहले से ही उत्पाद शुल्क लगाने वाले कानून - संसद - क्या इस विषय पर एक और कानून बना सकता है - धारा 4 - क्या अस्पष्ट है और इसलिए रद्द किए जाने योग्य है - नियम 6 के प्रावधान - क्या धारा 9(2) के विपरीत चलते हैं - ऐसा नियम - क्या मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर में अनियंत्रित शक्ति निहित है),

माना गया कि उत्पादन उपकर अधिनियम 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 5 (1) आम तौर पर उन वस्तुओं को प्रदान करती है जिनके लिए एकत्रित उपकर के बराबर राशि होती है। अर्थात्, उपज के सुधार, विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाना है। दूसरी ओर, उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से एक विस्तृत प्रावधान है जो विशिष्ट शब्दों में विभिन्न उप-शीर्षों को निर्धारित करता है जिनके लिए उपकर को विनियोजित किया जाना है, हालांकि यह अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। इस खंड का बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दूर से भी यह प्रावधान नहीं करता है कि अधिनियम के तहत एकत्र किया गया उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा बनने के योग्य है, जैसा कि भारत

के संविधान 1950 के अनुच्छेद 266 द्वारा अनिवार्य है। इस उप-धारा की कुंजी बहुत ही प्रारंभिक और भौतिक शब्दों द्वारा प्रदान की गई है, अर्थात्, "इस अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क की आय के बराबर राशि।" इससे तुरंत यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि इस तरह से एक अभिन्न अंग है और संसद द्वारा विनियोजित संग्रह के खर्चे बराबर समतुल्य राशि कम हो अधिनियम की धारा 5 में वर्णित वस्तुओं और उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए एक कानून बनाने के बाद अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान में कहीं भी कोई अलग फंड या फोरम प्रदान नहीं किया गया है, जिसमें यहां लगाए गए उपकर की आय को जमा किया जाना है। एक बार ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 266 के स्पष्ट आदेश के तहत, संग्रह किया गया यह अधिनियम आवश्यक रूप से भारत की संचित निधि में जाना चाहिए। वास्तव में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य उत्पाद शुल्कों और करों की तरह यहां उपकर भी पहले भारत की संचित निधि का हिस्सा बनेगा और उसके बाद कानून के अनुसार संसद द्वारा विनियोग किया जाएगा। (अंश)।

माना गया कि किसी अधिरोप का निर्णय संबंधित अधिनियम के संपूर्ण प्रावधानों के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर किया जाना चाहिए, न कि केवल लेवी का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली के संदर्भ में। इसलिए, "उपकर" शब्द का मात्र उपयोग न तो निर्णायक है और न ही निश्चयक। वास्तव में धारा 3(2) स्पष्ट रूप से इस शुल्क को उत्पाद शुल्क के रूप में नामित करती है और फिर धारा 4 इस अधिनियम के तहत किसी भी उपज पर लगाए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद शुल्क को उदग्रहण करती है। जब संसद ने स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि उपकर उत्पाद शुल्क का एक कर्तव्य है तो उसे अनिवार्य रूप से उसके अधिदेश में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यहां प्रयुक्त शब्दावली वास्तव में इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि विधानमंडल का इरादा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के बजाय उत्पाद शुल्क लगाना था। (पैरा 9)।

माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 272 की सरल भाषा से भी यह स्पष्ट है कि उसमें उल्लिखित उत्पाद शुल्क का राज्यों को वितरण स्वचालित नहीं है। दायित्व, यदि कोई हो, तभी उत्पन्न होता है जब संसद कानून द्वारा ऐसा प्रावधान करती है। इसमें फिर से स्थिति भौतिक रूप से भिन्न नहीं है और किसी भी मामले में अनुच्छेद 266 के अनुरूप है जिसमें भारत की संचित निधि से विनियोग हमेशा विधि के अनुसार और संविधान द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्यों और ढंग से होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि अनुच्छेद 272 के तहत, संसद ने इस अधिनियम के तहत एकत्रित उत्पाद शुल्क को राज्यों को वितरित करने के लिए स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं बनाया है और इसलिए, उन्हें उपकर का कोई हिस्सा नहीं मिलता है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अनुच्छेद 272 के आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया है या यहां लगाया गया उपकर कर या उत्पाद शुल्क नहीं है जैसा कि संसद द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित है। (पैरा 10)

माना गया कि कानून बनाना या अन्यथा बनाना स्पष्ट रूप से विधायी नीति का मामला है जिस पर टिप्पणी करना या निर्णय देना न्यायालय का क्षेत्र नहीं है। वास्तव में समग्र रूप से उत्पाद उपकर अधिनियम की जांच से पता चलता है कि इस उद्देश्य के लिए एक अलग अधिनियम आवश्यक था और किसी भी मामले में वांछनीय था और यदि संसद ने अपने विवेक से ऐसा किया था, तो यह तर्क देना व्यर्थ है कि समान प्रावधानों को इसमें उत्पाद शुल्क लगाने वाले मौजूदा कानून में सम्मिलित किया जाए। (पैरा 11)

माना गया कि इस तथ्य के अलावा कि धारा 4 की भाषा में कोई अंतर्निहित अस्पष्टता नहीं है, यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि किसी प्रावधान को केवल व्याख्या में कुछ कठिनाइयों के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि धारा 4 को सीमांत क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा कुछ सटीक या त्रुटिहीन व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह प्रावधान संविधान का उल्लंघन करता है।

(पैरा 16)

माना जाता है कि अधिनियम की योजना से पता चलता है कि धारा 8 एक मिल के मालिक पर पिछले महीने के दौरान मिलों में उपभोग की गई या प्रसंस्करण के तहत लाई गई या निकाली गई उपज के संबंध में कलेक्टर को अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने का दायित्व देती है। इसकी उपधारा (2) और (3) में यह आवश्यक है कि यह रिटर्न प्रत्येक माह के सातवें दिन से पहले प्रस्तुत किया जाएगा और इसे ऐसे प्रारूप में बनाया जाएगा और इस तरह से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। अब यह स्पष्ट है कि उत्पाद उपकर पुल 1969 का नियम 6 उस क्षेत्र में लागू होता है जहां मिल का अधिभोगी धारा 8 द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य को करने में विफल रहा है। यह केवल वहां है जहां निर्धारित अनुसार कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत को गलत या दोषपूर्ण माना जाता है जिससे नियम 6 में दिए गए तरीके से देय राशि का आकलन करने का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह न तो असामान्य है और न ही अनुचित है कि कर या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता पर प्राधिकरण सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए, ऐसी विफलता में आवश्यक रूप से दंडात्मक या खतरनाक परिणाम शामिल होते हैं जो ऐसा करने वाले प्राधिकारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किए गए मूल्यांकन के बाद हो सकते हैं। नियम 6 सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह से विवेकाधीन छोड़ने की बजाय,

वास्तव में एक बंधन और दिशानिर्देश देता है कि अधिभोगी द्वारा देय राशि उससे लगाए गए और एकत्र किए गए उपकर की मासिक औसत राशि के आधार पर होगी। ठीक पूर्ववर्ती बारह महीने। यह प्रावधान एक अनिर्देशित ओआई को निहित करने से बहुत दूर है; वास्तव में अनुचित विवेक स्पष्ट रूप से समान रूप से प्रसारित होता है।

(पैरा 19).

माना गया कि धारा 9(2) के परंतुक और नियम 6 के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में दोनों प्रावधान एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। प्रावधान थोड़ा अलग क्षेत्र में काम करता है जहां कलेक्टर शुल्क का आकलन उस राशि से अधिक राशि पर करता है जिस पर रिटर्न के आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा करने से पहले वह सही साबित करने के लिए कब्जाधारी को एक अवसर देगा। और रिटर्न की पूर्णता. नियम 6 के तहत मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों में न तो कोई मनमानी है और न ही धारा 9 या अधिनियम की किसी अन्य धारा के प्रावधानों का कोई उल्लंघन है। इसलिए, नियम 6 अंतर्विरोध है।

(पैरा 20)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि :—

- (a) एक रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो उसने प्रोड्यूस सेस अधिनियम, 1966 की धारा 3 (2) और धारा 4 , और प्रोड्यूस सेस नियम , 1969 के नियम 6 को घोषित करते हुए, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अमान्य घोषित कर दिया हो।
- (b) उन्होंने पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की। दिनांक 27 दिसंबर, 1972 (अनुलग्नक 'बी' में

शामिल) और दिनांक 4 दिसंबर, 1973 (अनुबंध
'इ');

- (c) वह उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं से किसी भी उपकरण का आकलन करने और वसूल करने से रोकने के लिए परमादेश या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है ;
- (d) कोई भी रिट, आदेश या निर्देश जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो, वह प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं से कोई उपकरण एकत्र न करने का निर्देश जारी कर सकता है ; और
- (e) इस रिट याचिका की खर्च भी वह याचिकाकर्ताओं को दे सकती है।

इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मूल्यांकन पर रोक लगाने और प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को वापस लेने की कृपा करेगा।

R. याचिकाकर्ताओं के लिए वकील एल बत्ता और वकील एनके ज़ख्मी ।

प्रतिवादी की ओर से वकील कुलदीप सिंह ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एसएस संधवालिया, सीजे

1. उत्पाद उपकरण अधिनियम, 1966 की धारा 3(2) और धारा 4 की संवैधानिक वैधता और इसकी धारा 20 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 6 की संवैधानिक वैधता तैंतालीस के इस सेट में चुनौती का प्राथमिक और वास्तव में एकमात्र विषय है। संबंधित रिट याचिकाएँ।

2. जैसा कि स्पष्ट है, मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है और इसलिए तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ ही पर्याप्त होगा। 1974 के सीडब्ल्यूपी नंबर 35 मेसर्स धनपत ऑयल एंड जनरल मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में दिए गए कथनों का विज्ञापन करना पर्याप्त होगा , जो विशिष्ट हैं, यदि दूसरों के समान नहीं हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं मूंगफली, कपास-बीज, सरसों और अन्य तिलहनों से तेल निकालने का व्यवसाय करते हैं और सब्जी और अन्य आवश्यक तेलों के विक्रेता भी हैं। अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने 29 सितंबर, 1972 को एक नोटिस, अनुलग्नक 'ए' जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और लगाए गए उपकरण से संबंधित जांच के संबंध में उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता थी। उत्पाद उपकरण अधिनियम 1966 के तहत, (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)। हालाँकि, याचिकाकर्ता कथित प्रामाणिक विश्वास के साथ इसका अनुपालन करने में विफल रहे कि उनका व्यवसाय अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। बाद में 22 दिसंबर 1972 को, अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने याचिकाकर्ताओं को एक नोटिस (अनुलग्नक 'बी' के माध्यम से) जारी किया, जिसमें उनसे कारण बताने की मांग की गई कि रिटर्न दाखिल करने और उपकरण जमा करने में उनकी विफलता के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। उन पर। इस पर याचिकाकर्ताओं ने उत्तर दिया, - अनुलग्नक 'सी' के माध्यम से प्रतिवादियों के उन पर उपकरण लगाने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया है। हालाँकि, 3 सितंबर, 1973 को एक अन्य संचार, अनुलग्नक 'डी', तब याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में उनके सामने उपस्थित होने के लिए सहायक

कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न मांगों की थीं। उसके बाद स्थगन. हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने उपकर जमा नहीं किया और न ही उन्होंने इस आधार पर कारण बताओ नोटिस के अनुसार रिटर्न दाखिल किया कि उत्तरदाताओं के पास उपकर लगाने और वसूल करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उनके द्वारा निर्मित और उनके व्यवसाय में बेचे जाने वाले उत्पाद। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उन प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी जिसके तहत उपकर लगाया जाता है।

3. अनिवार्य रूप से तर्क और विवाद आवश्यक रूप से अधिनियम के लागू प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए और इन्हें पहले संदर्भ की सुविधा के लिए निर्धारित किया जा सकता है:

“5.3. उपकर लगाना”

(1) * * * *

- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दूसरी अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक उपज पर, ऐसी दर पर उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा, जो संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से अधिक न हो। उसके कॉलम 3, के रूप में। केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है

बशर्ते कि जब तक ऐसी दर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तब तक उत्पाद शुल्क उक्त अनुसूची के कॉलम 4 में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर लगाया और एकत्र किया जाएगा।...

(4) वे व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे : किसी भी उपज पर इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले प्रत्येक सीमा शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा ऐसी उपज को भारत से निर्यात किया जाता है और किसी भी उपज पर इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाएगा। उस मिल के अधिभोगी द्वारा देय होगा जिसमें ऐसी उपज का उपभोग या निष्कर्षण किया जाता है।

4. अब श्री आरएल बत्ता द्वारा उठाई गई संविधान की चुनौती का 5वां भाला-प्रमुख मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 3(2) के खिलाफ निर्देशित है। यहां तर्क का मूल यह है कि सार और सार में अधिनियम की धारा 3(2) के तहत लेवी को उत्पाद शुल्क के रूप में स्टाइल किया गया है, लेकिन यह वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक शुल्क है। यह बताने की कोशिश की गई थी कि इस उपकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के बदले में अधिनियम की धारा 5(1) और (2) में प्रावधान किया गया है जो उपकरण की आय के आवेदन का प्रावधान करता है। इसलिए, कुछ दृढ़ता के साथ यह तर्क दिया गया कि इस लेवी को कर या उत्पाद शुल्क के रूप में लेबल करना स्पष्ट रूप से भ्रामक है और निर्णायक नहीं हो सकता है, असली परीक्षा लेवी की वास्तविक प्रकृति है। इन परिसरों पर, श्री बट्टा ने तब तर्क

दिया कि उपकर एक शुल्क की प्रकृति में है जिसका उपयोग अधिनियम की धारा 5(2) के खंड (ए) से (एन) में दिए गए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना है। संसद के पास इसे लागू करने की कोई विधायी शक्ति नहीं है। वकील के अनुसार यह लेवी मुख्य रूप से कृषि उपज पर शुल्क की प्रकृति में है, इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से कृषि शिक्षा और अनुसंधान, संरक्षण सहित कृषि से संबंधित राज्य सूची की प्रविष्टि 14 के आधार पर राज्य विधायिका में निहित है। कीटों के विरुद्ध और पौधों की बीमारियों की रोकथाम।

5. इस तर्क को स्थापित करने के लिए कि मूल रूप से धारा 3(2) के तहत लेवी एक कर या उत्पाद शुल्क नहीं है, बल्कि एक शुल्क है, श्री बट्टा ने कुछ संकेतों की सहायता के लिए कॉल करने का प्रयास किया था। यहां दलील यह थी कि धारा 5(1) और (2) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम के तहत लगाया गया उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगा और इसे निर्धारित किया गया था। सामान्य रूप से और विशेष रूप से धारा 5(2) के खंड (ए) से (एन) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपज के सुधार, विकास और विपणन को बढ़ावा देना। वकील ने तर्क दिया कि धारा 5 के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर उपकर को संघ के अन्य सामान्य राजस्व की तरह विनियोजित नहीं किया जा सकता है जो अपनी पहचान खो देते हैं और इसके संचित निधि का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रस्ताव के लिए भरोसा द हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1) और विशेष रूप से रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 और 22 में की गई टिप्पणियों पर रखा गया था।

6. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क

का आधार अधिनियम की धारा 5(1) और (2) पर आधारित है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए उपरोक्त को निर्धारित करना सबसे अच्छा है। संदर्भ सुविधा हेतु प्रावधान:-

"एस. 5(1) इस अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क की आय के बराबर राशि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी धन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संग्रह की खर्चों से घटाकर, यह अधिनियम, संसद द्वारा कानून द्वारा उचित विनियोजन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा उन उपायों के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो उस सरकार की राय में, सुधार, विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं। उपज का विपणन.

(2) विशेष रूप से, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क की आय का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, अर्थात्: -

- (a) कृषि, औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करना, सहायता करना या प्रोत्साहित करना, जिसमें किसी भी उपज से प्राप्त उत्पादों के उपयोग पर अनुसंधान शामिल है;
- (b) कृषकों, उत्पादकों और मिल मालिकों को तकनीकी सलाह प्रदान करना;
- (c) फसलों की खेती और भंडारण के बेहतर तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना ;

(आईआरटीएलएच. 1961 एससी 459.

- (d) फसलों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, परीक्षण और वितरण या ऐसे कार्य में सहायता करना;
- (e) खेत और भंडारण दोनों में, फसलों के कीड़ों और अन्य कीटों और बीमारियों के नियंत्रण में सहायता करना;
- (f) भारत और विदेशों में उपज और उससे प्राप्त उत्पादों के विपणन में सुधार को बढ़ावा देना, जिसमें उपज और उससे प्राप्त उत्पादों के लिए ग्रेड मानकों की स्थापना और अपनाना शामिल है;
- (g) सभी प्रासंगिक मामलों पर किसानों, उत्पादकों, डीलरों और मिलों के कब्जेदारों से आंकड़े एकत्र करना और फसलों के पूर्वानुमान में सुधार को बढ़ावा देना और फसलों और उनसे प्राप्त उत्पादों से संबंधित सभी प्रासंगिक आंकड़े तैयार करना ।
- (h) ऐसे संस्थानों, फार्मों और स्टेशनों को बनाए रखना और उनके रखरखाव में सहायता करना, जिन्हें केंद्र सरकार आवश्यक समझे;
- (i) फसलों की खेती में सुधार (खेती की जाने वाली फसलों की सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त किस्मों पर सलाह देने सहित) और फसलों और उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग करने वाले उद्योगों के सुधार से जुड़े सभी मामलों पर सलाह देना और सहायता प्रदान करना;
- (j) किसी भी जुड़े उद्योग में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

- (k) उत्पादकों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय अपनाना जो व्यावहारिक हों ;
- (l) कृषकों, उत्पादकों, मिल मालिकों और उपभोक्ता संगठनों की स्थापना का आयोजन करना;
- (m) उपज और उससे प्राप्त उत्पादों के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों की स्थापना को सहायता देना और प्रोत्साहित करना ;
- (n) कोई अन्य उपाय अपनाना जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या उचित समझे।

7. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 5(1) व्यापक रूप से उन उद्देश्यों को प्रदान करती है जिनके लिए एकत्र किए गए उपकर के बराबर राशि को लागू किया जाना है, अर्थात्, उपज के सुधार, विकास और विपणन को बढ़ावा देना। दूसरी ओर उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से एक विस्तृत प्रावधान है जो विशिष्ट शब्दों में विभिन्न उप-शीर्षों को निर्धारित करता है जिनके लिए उपकर को विनियोजित किया जाना है, हालांकि यह उप-धारा के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। (1) अधिनियम की धारा 5 का।

8. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि धारा 5 की उपधारा (1) का सटीक और गहराई से अध्ययन किया जाए तो इस तर्क का मूल तथ्य कि अधिनियम के तहत लगाया गया उपकर भारत की संचित निधि में नहीं जाता है, सीधे तौर पर पलट जाता है। इसका बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि

इससे दूर-दूर तक यह प्रावधान नहीं है कि अधिनियम के तहत एकत्र किया गया उपकर भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया आदेश है। मेरे विचार से, इस उपधारा की कुंजी बहुत ही प्रारंभिक और भौतिक शब्दों द्वारा प्रदान की गई है, अर्थात्, "इस अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क की आय के बराबर राशि"। इससे तुरंत यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि इस तरह से एक हिस्सा और पार्सल बनने के बाद संग्रह की खर्चों से कम की गई समतुल्य राशि को विनियोजित किया जाना है। अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित वस्तुओं और उद्देश्यों के उपयोग के लिए कानून बनाने के बाद संसद। यहां जो विशेष महत्व है वह यह है कि अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान में कहीं भी कोई अलग फंड या फोरम प्रदान नहीं किया गया है, जिसमें यहां लगाए गए उपकर की आय को जमा किया जाना है। वास्तव में श्री बत्ता को यह स्वीकार करना पड़ा कि कृषि उपज विपणन अधिनियम (उसकी धारा 26 और 28, जिसका संदर्भ सादृश्य के माध्यम से दिया गया था) के प्रावधानों के विपरीत, इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसके निर्माण का आदेश दे सके। अलग निधि जिसमें उपकर जमा किया जाना है। एक बार ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 266 के स्पष्ट आदेश के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किया गया संग्रह आवश्यक रूप से भारत के समेकित कोष में जाना चाहिए। इसे और भी स्पष्ट एवं प्रकट किया गया है प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा रिटर्न में अपनाए गए स्पष्ट रुख से। इसके पैराग्राफ 12 (ii) में स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए कहा गया है कि यहां लगाया गया लेवी भारत के समेकित कोष में नहीं जाएगा और सामान्य राजस्व के साथ विलय हो जाएगा, यह बताया गया है कि उपकर विशिष्ट

शीर्ष के तहत एकत्र और जमा किया जाता है। यह निम्नानुसार चलता है:-

एफ

"अस्वीकृत। उत्पाद शुल्क को उपकर के रूप में एकत्र किया जाता है और विशिष्ट शीर्ष यानी 'II-केंद्रीय उत्पाद शुल्क •- D-वस्तुओं पर उपकर-तेल/कोपरा पर उपकर' के तहत जमा किया जाता है।"

इसलिए, इन सभी कारकों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम के तहत उपकर पहले संघ के सामान्य राजस्व में जाएगा और भारत के समेकित कोष का हिस्सा बनेगा, जिसे निर्दिष्ट शीर्ष के तहत एकत्र किया जाएगा, अर्थात्, "II-केंद्रीय उत्पाद शुल्क" कर्तव्य—डी—

वस्तुओं पर उपकर - तेल/कोपरा पर उपकर।" ऐसा होने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) और समान रूप से उपधारा (2) में यह नहीं कहा गया है कि उपकर से राजस्व संचित निधि में नहीं जाएगा, बल्कि संक्षेप में वे उपज के सुधार, विकास और विपणन को बढ़ावा देने के प्रयोजनों के लिए उक्त निधि से विनियोग की पद्धति और तरीके प्रदान करते हैं। जब इस कोण से देखा जाता है, तो "इस अधिनियम के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए शुल्क की आय के बराबर राशि" शब्दों का महत्व उभरता है और इस प्रावधान की व्याख्या करते समय इसे सबसे आगे रखा जाना चाहिए। यदि अधिनियम के तहत उपकर एक अलग निधि बनाने के लिए होता, तो जाहिर तौर पर उसके बराबर राशि निकालने या संचित निधि से इसके विनियोग का कोई सवाल ही नहीं उठता। समान महत्व का तथ्य यह है कि धारा 5(1) आगे यह प्रावधान करती है कि उपरोक्त राशि को पहले केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संग्रह की खर्च से कम किया जाना है और उसके बाद केंद्र द्वारा प्राप्त किसी भी धन में वृद्धि की जानी है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार .

हालाँकि, एक स्पष्ट नोटिस की आवलिए फिर से स्वचालित नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग पर निर्भर है जैसा कि अन्य समान मामलों में होता है। भारत की संचित निधि. इस सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुख्य तर्क से बिल्कुल नीचे उतर जाता है कि अधिनियम के तहत उपकर भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं बनता है और इसलिए, इसमें आवश्यक संकेतकों में से एक का अभाव है। कर या उत्पाद शुल्क होना। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है

यह स्पष्ट है कि अन्य उत्पाद शुल्कों और करों की तरह, यहां उपकर भी पहले भारत के समेकित कोष का हिस्सा होगा और उसके बाद कानून के अनुसार संसद द्वारा विनियोजन किया जाएगा।

शकता यह है कि उपरोक्त राशियों का उपयोग धारा 5 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए फिर से स्वचालित नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग पर निर्भर है जैसा कि अन्य समान मामलों में होता है। भारत की संचित निधि. इस सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुख्य तर्क से बिल्कुल नीचे उतर जाता है कि अधिनियम के तहत उपकर भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं बनता है और इसलिए, इसमें आवश्यक संकेतकों में से एक का अभाव है। कर या उत्पाद शुल्क होना। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है

यह स्पष्ट है कि अन्य उत्पाद शुल्कों और करों की तरह, यहां उपकर भी पहले भारत के समेकित कोष का हिस्सा होगा और उसके बाद कानून के अनुसार संसद द्वारा विनियोजन किया जाएगा।

9. इसके बाद श्रीमान बट्टा ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए अधिनियम के शीर्षक और उसमें इस्तेमाल की गई शब्दावली पर पलटवार किया कि इसके तहत किया गया शुल्क वास्तव में एक शुल्क था,

न कि कोई कर या उत्पाद शुल्क। इसमें मूल जोर "उपकर" शब्द के उपयोग पर था। कुछ जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि इस नामकरण का न तो मैली, न ही हमेशा के लिए उपयोग किया जाता है। एक शुल्क और कर के लिए नहीं। मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। यह हिं गिर रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1) (सुप्रा) में टिप्पणियों से भी अच्छी तरह से तय और स्पष्ट है, जिस पर याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से भरोसा किया था कि पूरे प्रावधानों के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर एक अधिरोपण का फैसला किया जाना है। संबंधित अधिनियम के बारे में, न कि केवल लेवी का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली के संदर्भ में। निर्णय किए गए विरामों के संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा। हिं गिर रामपुर कोयला मामले (सुप्रा) में, उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम द्वारा लगाया गया उपकर, उक्त क़ानून के सभी प्रावधानों पर विचार करने पर, न तो कर और न ही उत्पाद शुल्क बल्कि एक शुल्क माना गया था। हालाँकि, गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम के तहत, भले ही उसमें इस्तेमाल की गई शब्दावली "उपकर" थी, इसे अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एंड केलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद बनाम में उनके प्रभुत्व द्वारा आयोजित किया गया था? गुजरात राज्य (2) कि यह एक कर था, शुल्क नहीं। शिंदफे ब्रदर्स आदि बनाम डिप्टी कमिश्नर, रायचूर (3) मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मान लिया गया है कि मैसूर स्वास्थ्य उपकर अधिनियम के तहत लेवी एक कर थी न कि शुल्क। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि "उपकर" शब्द का मात्र उपयोग न तो निर्णायक है और न ही निर्णायक। वास्तव में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कुलदीप सिंह यह तर्क देने में मजबूत आधार पर थे कि धारा 3(2) स्पष्ट रूप से इस शुल्क को उत्पाद शुल्क के रूप में नामित करती है और फिर धारा 4 इस अधिनियम के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क के तहत लगाए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद शुल्क को संदर्भित करती है। 'उत्पादन करना। जब संसद ने स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि उपकर उत्पाद

शुल्क है, तो उसके अधिदेश में उचित महत्व अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालने को इच्छुक हूँ कि यहां इस्तेमाल की गई शब्दावली वास्तव में इस तथ्य का सूचक है कि विधानमंडल का इरादा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के बजाय उत्पाद शुल्क लगाना था।

10. श्रीमान एलआर। बीएल.;टी बट्टा ने तब कहा था कि यहां उपकर को हालांकि उत्पाद शुल्क के रूप में लेबल किया गया है, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 272 बनाम का उल्लंघन होगा। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 5 के कारण, राज्य अपने क्षेत्र के भीतर एकत्र शुल्क के अपने हिस्से को सुरक्षित करने के हकदार नहीं होंगे और इस तरह अनुच्छेद 272 के आदेश का उल्लंघन होगा। इस विवाद की सराहना करने के लिए किसी को अनुच्छेद 272 अवश्य पढ़ना चाहिए-

“272. संघ सूची में उल्लिखित औषधीय और शौचालय तैयारियों पर उत्पाद शुल्क के अलावा अन्य उत्पाद शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा, लेकिन, यदि संसद कानून द्वारा ऐसा प्रावधान करती है, तो इसका भुगतान किया जाएगा। भारत की संचित निधि उन राज्यों को दी जाती है जिन पर शुल्क लगाने वाला कानून उस शुल्क की पूरी शुद्ध आय के पूरे या किसी हिस्से के बराबर राशि प्रदान करता है, और उन राशियों को वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। जैसा कि ऐसे कानून द्वारा तैयार किया जा सकता है।”

इसकी स्पष्ट भाषा से भी यह स्पष्ट है कि राज्यों को यहां उल्लिखित उत्पाद शुल्क का वितरण स्वचालित नहीं है। दायित्व, यदि कोई हो, तभी उत्पन्न होता है जब संसद कानून द्वारा ऐसा प्रावधान करती है। इसमें फिर से स्थिति भौतिक रूप से भिन्न नहीं है और किसी भी मामले में अनुच्छेद 266 के अनुरूप है जिसमें भारत की संचित निधि से विनियोग हमेशा कानून के अनुसार और संविधान द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्यों और तरीके से होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि अनुच्छेद 272 के तहत, संसद ने इस अधिनियम के तहत एकत्रित उत्पाद शुल्क को राज्यों को वितरित करने के लिए स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं बनाया है और इसलिए, उन्हें उपकर का कोई हिस्सा नहीं मिलता है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अनुच्छेद 272 के जनादेश का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया है या यहां लगाया गया उपकर कर या उत्पाद शुल्क नहीं है जैसा कि संसद द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित है।

11. इस संदर्भ में लगभग अंतिम तर्क के रूप में श्री बत्ता ने तब तर्क दिया था कि मौजूदा कानूनों, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कर अधिनियम और उत्पाद शुल्क लगाने वाले अन्य समान कानूनों के सामने संसद की कोई आवश्यकता नहीं थी।

नया कानून बनाएं और किसी भी एक कानून के प्रावधानों के तहत ऐसा शुल्क लगाया जाए। विवाद में स्पष्टतः दम नहीं है। कानून का अधिनियमन या अन्यथा स्पष्ट रूप से विधायी नीति का मामला है जिस पर टिप्पणी करना या निर्णय देना इस न्यायालय का क्षेत्र नहीं है। वास्तव में उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 की समग्र जांच से पता चलता है कि इस उद्देश्य के लिए एक अलग अधिनियम आवश्यक था और किसी भी मामले में वांछनीय था और यदि संसद ने अपने विवेक से ऐसा किया है तो

यह वकील की ओर से व्यर्थ है। तर्क है कि उत्पाद शुल्क लगाने वाले मौजूदा कानूनों में समान प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए थे।

12. प्रतिवादी भारत संघ के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह के प्रति निष्पक्षता में, मुझे ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि उत्पाद उपकर अधिनियम सूची। के आइटम 84 के मद्देनजर पूरी तरह से संसद की विधायी शक्तियों की क्षमता के भीतर था। संविधान की सातवीं अनुसूची। इस तथ्य के अलावा कि उपकर, उत्पाद शुल्क का एक कर्तव्य होने के नाते, पूरी तरह से प्रविष्टि के भीतर आएगा, वकील ने विधायी क्षमता के संदर्भ में मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत पर भी भरोसा किया था और तर्क दिया था कि भले ही कुछ आकस्मिक और राज्य सूची में निर्धारित विषयों के सीमांत ओवरलैपिंग के कारण, प्रावधानों की संवैधानिकता प्रभावित नहीं होगी यदि सार और सार में विषय प्रविष्टि 84 के दायरे में आता है। इस प्रस्ताव के लिए *चतुरभाई एम. पटेल बनाम पर भरोसा करना उचित ही था। भारत संघ और अन्य।*

13. श्री. 1944 का उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम। फिर से चतुरभाई एम. पटेल के मामले (सुप्रा) का संदर्भ दिया गया, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 को अधिनियमित करने की संसद की विधायी क्षमता के आधार पर दी गई संवैधानिक चुनौती को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया था।

14. अंत में इस संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया था कि 1966 का उत्पाद उपकर अधिनियम न तो नया था और न ही असामान्य अधिभार था और वास्तव में यह बताया गया था कि वास्तव में यह क़ानून एक संशोधनकारी या समेकित प्रकृति का है। यह प्रस्तुत किया

गया कि वर्तमान अधिनियम एक संख्या का स्थान लेता है ।

पहले के क़ानूनों में व्यक्तिगत रूप से कपास, लाख, नारियल और तिलहन आदि पर समान मामले तय किए गए थे। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के स्पष्ट बयानों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद में स्पष्ट योग्यता है जिसके कारण इसे अधिनियमित किया गया। वर्तमान क़ानून. यह पहलू वास्तव में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आरएल बत्ता द्वारा किसी गंभीर चुनौती का मामला नहीं था और न ही हो सकता है। विधेयक के अधिनियमन के उद्देश्यों की सराहना करने के लिए उद्देश्यों और उनके कारणों के विवरण को विस्तार से दोहराने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता:

-

“भारतीय कपास उपकर समिति अधिनियम, 1923, भारतीय लाख उपकर अधिनियम, 1930, भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944, तिलहन समिति अधिनियम, 1946, 1 अप्रैल, 1966 से प्रभावी नहीं होंगे, जिस तारीख को भारतीय केंद्रीय कपास उन अधिनियमों के तहत गठित समिति और भारतीय लाख उपकर समिति, भारतीय केंद्रीय नारियल समिति और भारतीय केंद्रीय तिलहन समिति भंग हो जाएंगी, और इन उत्पादों पर उपकर की वसूली जारी रखने के लिए कोई विधायी मंजूरी नहीं होगी। 31 मार्च 1966 के बाद.

(2) हालाँकि समितियों को समाप्त कर दिया गया है, समितियों द्वारा किया जाने वाला कार्य 31 मार्च, 1966 के बाद भी जारी रहेगा। इन समितियों के अनुसंधान संस्थान और स्टेशन और अन्य अनुसंधान परियोजनाएं भारतीय कृषि परिषद के प्रशासनिक

नियंत्रण में आ जाएंगी। अनुसंधान और विकास, विपणन और अन्य कार्यों से संबंधित कार्य सीधे खाद्य और कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग द्वारा देखे जाएंगे, और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विकास परिषदों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान संस्थानों के रखरखाव और अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को उचित अनुदान दिया जाएगा। संशोधित व्यवस्था के तहत, अनुसंधान और विकास का एक प्रभावी कार्यक्रम बनाने के लिए इन उत्पादों पर बड़ा निवेश आवश्यक होगा। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि कमोडिटी समितियों को समाप्त करने के बाद भी उपज पर उपकर लगाया जाता रहे।

(3) तदनुसार, विधेयक इन उपजों पर उपकर की वसूली जारी रखने का प्रयास करता है।

(4) अवसर को प्रकृति को सरल बनाने के लिए भी लिया गया है; उपज पर लगाए गए उपकर को खत्म करने और उपज की वर्तमान कीमतों के अनुरूप लगाए जाने वाले उपकर की दर का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए।"

15. उपरोक्त कारणों से मैं यह निष्कर्ष निकालूंगा कि अधिनियम की धारा 3 के बुनियादी प्रावधानों के खिलाफ बहुआयामी हमले को निरस्त किया जाना चाहिए और इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा जाना चाहिए।

16. अब अधिनियम की धारा 4 के दायरे में आते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अपनी चुनौती में आधे-अधूरे मन से थे और हमले की प्रकृति भी उतनी ही खंडित थी। यह तर्क दिया गया कि इसके प्रावधान अस्पष्ट और अस्पष्ट थे और यह स्पष्टता से निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि क्या शुल्क उस मिल के मालिक द्वारा देय होगा जिसमें उक्त उपज का उपभोग किया जाता है या जहां से इसे निकाला जाता है, यदि वे भिन्न हैं। इस तथ्य के अलावा कि हम धारा 4 की भाषा में कोई अंतर्निहित अस्पष्टता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमें यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि किसी प्रावधान को केवल व्याख्या की कुछ कठिनाइयों के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि धारा 4 को सीमांत क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा कुछ सटीक या त्रुटिहीन व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह प्रावधान संविधान का उल्लंघन है। इसलिए, मुझे इसकी वैधता को समान रूप से बरकरार रखना चाहिए।

17. मामले के इस पहलू से अलग होने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मैं जिस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक हूं, उसे राजा ऑयल मिल्स, चोव्वा, कोनानोर और अन्य बनाम भारत संघ (5) में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से पर्याप्त समर्थन प्राप्त है।, जिसे लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा राजा ऑयल मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (6) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट फैसले में बरकरार रखा गया था।

18. अंततः अधिनियम की धारा 20 के तहत बनाए गए उत्पाद उपकर नियम 1969 के नियम 6 पर हमला किया गया है। यह नियम निम्नलिखित पद में है:-

“6. उपकर के निर्धारण के मुख्य बिंदु : जहां किसी मिल का

अधिष्ठाता उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा है, या निर्दिष्ट अवधि में एक रिटर्न जिसके बारे में कलेक्टर के पास विश्वास करने का कारण है कि वह गलत या दोषपूर्ण है, कलेक्टर अधिभोगी द्वारा देय राशि का आकलन उस अधिभोगी से ठीक पहले के बारह महीनों में लगाए गए और एकत्र किए गए उपकर की मासिक औसत राशि के आधार पर करेगा। वह महीना जिससे मूल्यांकन संबंधित है।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस प्रावधान को मुख्य चुनौती यह थी कि यह अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया कि नियम ने देय उपकर का आकलन करने के लिए कलेक्टर को अनिर्देशित और अव्यवस्थित शक्तियां प्रदान कीं।

19. सरसरी तौर पर विश्लेषण करने पर भी उपरोक्त तर्कों पर पानी नहीं फिर सकता। अधिनियम की योजना से पता चलता है कि धारा 8 पिछले महीने के दौरान मिलों में उपभोग की गई या प्रसंस्करण के तहत लाई गई या निकाली गई उपज के संबंध में कलेक्टर को अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए मिल के मालिक पर कर्तव्य रखती है। इसकी उप-धारा (2) और (3) में कहा गया है कि यह रिटर्न प्रत्येक महीने के सातवें दिन से पहले प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे फॉर्म में बनाया जाएगा और ऐसे तरीके से सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है। अब यह स्पष्ट है कि नियम 6 उस क्षेत्र में लागू होता है जहां मिल का अधिवासी धारा 8 द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा है। यह

केवल वहां है जहां निर्धारित के अनुसार कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि प्रस्तुत किया गया है तो माना जाता है कर्नल लेक्चरर द्वारा यह गलत या दोषपूर्ण है कि नियम 6 में दिए गए तरीके से देय राशि का आकलन करने का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह न तो असामान्य है और न ही अनुचित है कि कर या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता पर प्राधिकरण सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए, ऐसी विफलता में आवश्यक रूप से दंडात्मक या खतरनाक परिणाम शामिल होते हैं जो ऐसा करने वाले प्राधिकारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किए गए मूल्यांकन के बाद हो सकते हैं। हालाँकि, एक विशेष नोटिस की आवश्यकता यह तथ्य है कि नियम 6 सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह से विवेकाधीन छोड़ने से दूर है, वास्तव में यह निर्धारित करके एक बाधा और एक दिशानिर्देश देता है कि अधिभोगी द्वारा देय राशि उस पर होगी तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों में उससे लगाए गए और एकत्र किए गए उपकर की मासिक औसत राशि के आधार पर। यह प्रावधान किसी दिशाहीन या अनुचित विवेकाधिकार को निहित करना तो दूर, वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से सीमित करता है।

20. न ही मुझे धारा 9(2) के परंतुक और नियम 6 के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास दिखाई देता है। वास्तव में ये दोनों प्रावधान एक में हैं

एक दूसरे के पूरक की तरह. प्रावधान थोड़ा अलग क्षेत्र में काम करता है जहां कलेक्टर शुल्क का आकलन उस राशि से अधिक राशि पर करता है जिस पर रिटर्न के आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा करने से पहले वह कब्जाधारी को सही

साबित करने का अवसर देगा और रिटर्न की पूर्णता. इसलिए, मेरा विचार है कि नियम 6 के तहत मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर में निहित शक्तियों में न तो कोई अरबी लापरवाही है और न ही धारा 9 या अधिनियम की किसी अन्य धारा के प्रावधानों का कोई उल्लंघन है। इसलिए, नियम 6 को अधिकारातीत माना जाना चाहिए।

21. अंत में, श्री बत्ता ने याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को इस आधार पर चुनौती देने का फैसला किया था कि उपकर लगाने के लिए कोई मशीनरी प्रदान नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा किए गए दावों को रद्द किया जाना चाहिए। वकील ने बताया कि अधिनियम 1966 में लागू हुआ था और इसके विभिन्न प्रावधानों ने इसके संग्रह के तरीके को नियमों के तहत निर्धारित तरीके से निर्धारित किया था, फिर भी तीन साल बाद तक उत्पादन उपकर नियम 1959 लागू नहीं हुए थे। फंसाया हुआ. तब यह बताया गया कि उक्त नियमों के तहत जिस कलेक्टर के समक्ष रिटर्न दाखिल किया जाना था और जिसे उसके तहत मूल्यांकन करना था, उसे 30 जुलाई, 1970 तक इस क्षेत्र के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, और अपीलीय प्राधिकारी को इसके तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। 21 अगस्त, 1972 को अधिसूचना जारी होने तक धारा 10। उपरोक्त परिसर में, वकील ने कहा कि सामग्री मशीनरी अस्तित्वहीन होने के कारण न तो धारा 8 के तहत कोई रिटर्न दाखिल किया जा सकता है और न ही उपकर का संग्रह और आकलन किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत । परिणामस्वरूप अपेक्षित मशीनरी के निर्माण से पहले की अवधि के संबंध में नोटिस को स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी के रूप में खारिज

कर दिया गया था।

22. विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क पर केवल उत्पाद उपकर अधिनियम की धारा 15 के स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर ध्यान दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भावार्थ में उद्धरण की भी आवश्यकता होगी

“15. लागू होने वाले कुछ अधिनियमों के प्रावधान। (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, जिनमें रिफंड और शुल्क से छूट से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जहां तक संभव हो, इस संबंध में लागू होंगे।

._ए

पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उत्पाद पर सीमा शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए, क्योंकि वे उस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को देय शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें रिफंड और शुल्क से छूट से संबंधित नियम भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो, किसी भी उपज पर उत्पाद शुल्क के लगाने और संग्रह के संबंध में लागू होंगे। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं क्योंकि वे उस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को देय शुल्क की वसूली और वसूली के संबंध में लागू होते हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत नए नियम बनाए जाने तक, उपरोक्त धारा 15 द्वारा पर्याप्त प्रावधान किए गए थे। यह गंभीरता से विवादित नहीं था कि वैधानिक नियम सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम के तहत भी मौजूद थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944। ऐसा होने पर यह याचिकाकर्ताओं के मुंह से झूठ नहीं बोलता है कि कर के संग्रह और मूल्यांकन के लिए मशीनरी में इतनी कमी थी कि उन्हें जारी किए गए नोटिस अमान्य हो गए। हालाँकि, इस संदर्भ में, मैं देख सकता हूँ कि प्रतिवादी भारत संघ के विद्वान वकील स्वयं यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष थे कि कानून के लागू होने के बाद कलेक्टर और अपीलीय प्राधिकारी की अधिसूचना में कुछ मामूली देरी हुई थी। नियम। विद्वान वकील ने माना, यह अधिनियम की धारा 16 के तहत डिफॉल्टरों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का सहारा न लेने के लिए पर्याप्त औचित्य होगा, जो अधिनियम के तहत उपकर के संग्रह और मूल्यांकन के संबंध में कुछ अपराध भी बनाता है।

परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि ये सभी रिट याचिकाएं बिना किसी योग्यता के हैं और इन्हें खारिज किया जाता है, हालांकि, इसमें शामिल प्रश्नों की कुछ जटिलताओं और नियमों की घोषणा के बाद प्रक्रियात्मक विवरणों को अधिसूचित करने में हुई देरी को देखते हुए, पार्टियों को खर्चे स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति एससी मितल.- मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा